



Neutral Citation No. - 2026:AHC:58483-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

विशेष अपील संख्या - 203/2026

सभाजीत यादवअपीलार्थी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्यप्रत्यर्थीगण

अपीलार्थी के अधिवक्ता: रमेश प्रसाद मिश्रा, रंजना

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 3

माननीय न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह,

माननीय न्यायमूर्ति विवेक सरन,

1. मूल याचिकाकर्ता/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.पी. मिश्रा और राज्य-प्रत्यर्थीगण के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. वर्तमान अंतः-न्यायालय अपील विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 13.01.2026 के आदेश (सभाजीत यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य; 2026:AHC:8134) के विरुद्ध उत्पन्न हुई है। उस आदेश के द्वारा, विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित आदेश के तहत रिट याचिका को खारिज कर दिया है:

"1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।

2 प्रारंभ में यह रिट याचिका वेतन भुगतान हेतु परमादेश जारी करने के लिए दायर की गई थी। कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया था।

3. याचिकाकर्ता का आगे यह मामला है कि उसकी सेवाओं को अन्य व्यक्तियों के साथ दिनांक 05.11.2004 के आदेश द्वारा समाप्त कर दिया गया था। संशोधन आवेदन स्वीकार होने के बावजूद, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने रिट याचिका में संशोधन नहीं किया है।

4. न्यायालय यह भी पाता है कि याचिकाकर्ता ने 2025 में पुनर्वहाली आवेदन के शपथ पत्र में अपनी आयु 56 वर्ष घोषित की है, जबकि उक्त आवेदन के साथ संलग्न उनके आधार कार्ड के अनुसार, उनकी जन्म तिथि 01.05.1961 दिखाई गई है, अतः वर्तमान में उनकी आयु लगभग 64 वर्ष है, इसलिए यह ऐसा मामला है जहां याचिकाकर्ता न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



कर रहा है। 5. न्यायालय यह भी संज्ञान लेता है कि दी गई परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता ने 2009 से इस रिट याचिका पर प्रभावी ढंग से दबाव नहीं डाला है, इसलिए इस विलंबित चरण में मांगी गई राहत प्रदान नहीं की जा सकती।

6. उपरोक्त के आलोक में, यह रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है, अतः इसे खारिज किया जाता है।”

3. तर्क यह है कि मूल याचिकाकर्ता/मुकदमेबाज पर रिट याचिका में संशोधन शामिल न करने के लिए उसके अधिवक्ता की ओर से हुई लापरवाही के परिणामों का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। इस सीमा तक कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि संशोधन आवेदन मूल याचिकाकर्ता द्वारा दायर किया गया था और उसे अनुमति दी गई थी, मुकदमेबाज का अपने अधिवक्ता द्वारा किए जाने वाले परिणामी कार्यों पर नियंत्रण काफी हद तक कम हो सकता है, न कि स्वयं मुकदमेबाज का।
4. आयु में विसंगति के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया है कि आयु के प्रकटीकरण के प्रयोजनों के लिए आधार कार्ड पर प्रकट विवरण पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। किसी भी मामले में, याचिकाकर्ता की पहचान के संबंध में किसी भी विवाद के अभाव में, न्यायालय को गुमराह करने के इरादे का निष्कर्ष बहुत कठोर और अनुचित है, विशेषकर वेतन बकाया आदि के संबंध में न्यायालय के समक्ष लाए गए विवाद को देखते हुए।
5. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेख का अवलोकन करने के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में सिद्धांततः एक त्रुटि हुई है, इस सीमा तक कि आक्षेपित आदेश के पैराग्राफ संख्या 3 में ही यह दर्ज किया गया था कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर संशोधन आवेदन को अनुमति दी गई थी। यह स्वीकार करना होगा कि मुकदमेबाज/याचिकाकर्ता पर उसके अधिवक्ता द्वारा अभिलेख में संशोधन शामिल न करने के परिणाम का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए।
6. उस कारण से, मुकदमेबाज को कोई अवसर दिए बिना रिट याचिका की बर्खास्तगी कठोर हो सकती है।
7. आयु के मुद्दे पर भी, हम पाते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश का आदेश पूरी तरह से सही नहीं हो सकता है क्योंकि आधार कार्ड पर अलग आयु प्रकट करके कोई लाभ प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया गया था। सेवा अवधि का संचालन सेवा अभिलेख में दर्ज आयु के अनुसार किया जाना चाहिए न कि इन कार्यवाहियों में दायर शपथ पत्र के अनुसार।
8. वर्तमान अंतः-न्यायालय अपील स्वीकार की जाती है, जो कि आज से 15 दिनों की अवधि के भीतर उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति को 1,000/- रुपये के हर्जाने के भुगतान के अधीन है।
9. हर्जाने के भुगतान (उपरोक्तानुसार) के अधीन, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उसके एक सप्ताह के भीतर संशोधन शामिल कर सकते हैं।
10. उपरोक्त अनुपालन के अधीन, रिट याचिका अपने मूल नंबर और स्थिति पर बहाल हो जाएगी और उसके बाद इसे उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जा सकता है।

(विवेक सरन, न्यायमूर्ति) (सौमित्र दयाल सिंह, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



20 मार्च, 2026

अभिलाष

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"